गन्ना किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: भारत गन्ना किसानों के हितों से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में कोई समझौता नहीं करेगा। भारतीय गन्ना किसानों को दी जाने वाली सरकारी मदद पर डब्ल्यूटीओ के पैनल ने अपनी रिपोर्ट में आपत्ति जाहिर की है। पैनल का मानना है कि डब्ल्यूटीओ की तय सीमा से अधिक भारतीय गन्ना किसानों को मदद दी जा रही है। भारत सरकार चीनी मिलों को चीनी के निर्यात पर प्रतिबंधित सब्सिडी मुहैया कराती है।

भारत ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए डब्ल्यूटीओ में अपील दायर करने की बात कही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट से चीनी क्षेत्र के लिए जारी नीति में कोई बदलाव नहीं होगा।

आस्ट्रेलिया, ब्राजील ने दी थी चुनौती

: वर्ष 2019 में आस्ट्रेलिया, ब्राजील व ग्वाटेमाला ने चीनी क्षेत्र से जुड़ी भारतीय नीति को डब्ल्यूटीओ में चुनौती दी थी। इस चुनौती के मद्देनजर डब्ल्यूटीओ ने पैनल का गठन किया था। पैनल ने 14 दिसंबर, 2021 को अपनी रिपोर्ट जारी की है।

कृषि क्षेत्र को मदद देने पर विकसित देशों को आपत्ति: विकसित देश भारतीय कृषि क्षेत्र की सरकारी मदद पर भी आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि भारत अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं करेगा।

बड़ा फैसला

- डब्ल्यूटीओ का पैनल किसानों को मिलने वाली मदद के खिलाफ
- सरकार ने डब्ल्यूटीओ में अपील करने का किया फैसला